भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंध में दिसंबर, 2020 माह का सारांश।

<u>जल जीवन मिशन (जेजेएम) में प्रगति</u>

दिसंबर, 2020 के दौरान लगभग 32.86 लाख घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2020-21 में अब तक 2.20 करोड़ घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इस माह के दौरान कार्यक्रम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 1,893.99 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

<u>स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण- II में प्रगति</u>

इस महीने के दौरान, बेसलाइन सर्वे (एलओबी) से लेफ्ट आउट श्रेणी के तहत 32,232 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और कोई वंचित न रहे (एनओएलबी) श्रेणी के तहत 1,59,134 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। साथ ही 10,727 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण दिसंबर, 2020 के दौरान किया गया था।

<u>एसबीएम-जी की निगरानी</u>

सचिव, डीडब्ल्यूएस ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण स्वच्छता और मिशन निदेशकों, एसबीएम (जी) के संबंधित एसीएस/ प्रधान सचिवों/ सचिवों के साथ अलग-अलग मध्य वर्ष की समीक्षा बैठकें लीं। एसबीएम-जी चरण- II के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ की गई।

<u>क्षेत्रीय दौरे</u>

इस विभाग के अधिकारियों और परामर्शदाताओं ने 17 से 19 दिसंबर, 2020 तक असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के जिलों में गांवों के दौरे किए ताकि स्वच्छ भारत मिशन चरण- II के तहत कार्यक्रम के वास्तविक क्षेत्रीय क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जा सके।

पंचायती राज संस्थाओं के साथ वार्तालाप

सरपंच संवाद "पीआरआई के साथ वार्तालाप" 15.12.2020 और 30.12.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। 33 सरपंचों/ जिला परिषद अध्यक्ष/ ब्लॉक प्रमुखों ने संवाद में भाग लिया। ओडीएफ स्थिरता, ओडीएफ प्लस और 15वें वित्त आयोग के फंड पर मुख्य चर्चा हुई।

जेजेएम की निगरानी

जल जीवन मिशन के तहत प्रगति की समीक्षा करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 10.12.2020 से 17.12.2020 तक बैठकों / कार्यशालाओं / कार्यक्रमों का आयोजन असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ किया गया था।